भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *115

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)

बेरोजगार व्यक्ति

***115. श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष दो करोड़ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की सभी संस्थाओं में विज्ञापित/अधिसूचित रिक्तियों की संख्या की तुलना में कितनी नियुक्तियां की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"बेरोजगार व्यक्ति" के संबंध में श्री राजेन्द्र धेड्या गावित द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 06-12-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *115 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) एवं (ख): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड 19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मानिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान ने 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन प्राप्त किया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 1.17 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.59 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत 26.46 लाख लाभार्थियों को 2641.46 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत नवंबर 2021 तक 31.28 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति भी उन्मुख हैं।

हाल ही में सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल- भारतीय तिमाही संस्थान आधारित सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। अप्रैल से जून 2021 की अवधि हेतु तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के प्रथम दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में 3.8 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि यह छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में यथा रिपोर्टित सामूहिक रूप से लिए गए इन क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ थी जो कि 29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। 152 प्रतिशत की सर्वाधिक प्रभावी वृद्धि आईटी/बीपीओ क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में यह 22 प्रतिशत, परिवहन में यह 68 प्रतिशत तथा निर्माण में यह 42 प्रतिशत रही है।

(ग) दिनांक 01.03.2020 की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार के विभागों में 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे। 256 संचालित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 9.20 लाख नियमित कर्मचारी थे।

पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों अर्थात कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए नामांकित अभ्यर्थियों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	**यूपीएससी**	**एसएससी**	**आरआरबी**	**योग**
2016-17	**5,735**	**68,880**	**27,538**	**1,02,153**
2017-18	**6,294**	**45,391**	**25,507**	**77,192**
2018-19	**4,399**	**16,748**	**17,680**	**38,827**
2019-20	**5,230**	**14,691**	**1,28,456**	**1,48,377**
2020-21	**4,214**	**68,891**	**5,764**	**78,869**
सकल योग	**25,872**	**2,14,601**	**2,04,945**	**4,45,418**

*****